

'Converge all skill development schemes under one ministry'

NEW DELHI: Various skill development schemes under the administrative control of different ministries should be handed over to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship for better outcome, a report has suggested.

"The NDA government has established a separate ministry for skill development. It is desirable that this central ministry takes the core elements from various ministries and pools them under one minister and under one budget, which could be around Rs 25,000 crore," a joint study by Assocham and Tata Institute of Social Sciences (TISS) said.

Currently, different skill development schemes still remain with various ministries and the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship is the coordinator.

The report also observed that the present Technical and Vocational Education and Training (TVET) system in India is facing some serious problems that can hamper the progress of Skill India Mission, which aims to train over 40 crore people by 2022.

"The country is facing a paradoxical situation where on the one hand young men and women with higher education entering the labour market are looking for jobs, and on the other, industries are complaining of the unavailability of appropriately skilled manpower," said the report. PTI

‘एक ही मंत्रालय के मातहत हों सभी कौशल विकास स्कीमें

नई दिल्ली, प्रेड: देश में तमाम कौशल विकास योजनाओं को एक ही मंत्रालय के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए। उद्योग चैंबर एसोसिएशन और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के अध्ययन में यह सुझाव दिया गया है। दोनों की ओर से तैयार साझा रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा करने से इन स्कीमों से बेहतर नतीजे मिल पाएंगे। फिलहाल अलग-अलग मंत्रालयों के मातहत कई कौशल विकास योजनाएं चल रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राजग सरकार ने कौशल विकास के लिए अलग से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय बनाया है। इसका लक्ष्य कई मंत्रालयों से संबंधित सभी योजनाओं और कार्यक्रमों एक ही

मंत्री के मातहत लाना था। इस मंत्रालय का बजट 25,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था। फिलहाल स्थित यह है कि कौशल विकास स्कीमें अलग-अलग मंत्रालयों के तहत बनी हुई हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय सिर्फ इनके बीच तालमेल की भूमिका निभा रहा है।

रिपोर्ट में यह भी निष्कर्ष निकाला गया है कि तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का तंत्र गंभीर समस्याओं से दो-चार है। ये हालात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्किल इंडिया अभियान की प्रगति की राह में रोड़े अटका सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश अजीब सी विरोधाभासी स्थिति का सामना कर रहा है।

हुनर विकास की योजनाओं के लिए एक ही मंत्रालय हो

नई दिल्ली | भिन्न मंत्रालयों के तहत जारी हुनर विकास की योजनाओं को बेहतर नतीजे के लिए कौशल विकास मंत्रालय को सौंप देना चाहिए। यह सुझाव एसोचैम व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की संयुक्त समिति ने दिया है।